समावेशी विकास के साथ आधुनिक छत्तीसगढ़ का निर्माण

गांव से लेकर शहरों तक बढ़ रहीं जनसुविधाएं, अधोसंरचना में हो रहे व्यापक बदलाव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने नई पहल के साथ विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। उनकी दूरदर्शी सोच से न केवल छत्तीसगढ़ सरकार के विकास कार्यक्रमों को गति मिली है, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य भर में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक नई शुरुआत भी हुई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से इस आदिवासी बाहुल्य राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों परिदृश्यों में बदलाव ला रहे हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका योजनाओं का एकीकरण कर सरकार ऐसी योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे इन वर्गों का तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। इन बड़े प्रयासों के साथ, एक तरह से सरकार समावेशी, जन-प्रथम शासन के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय के गतिशील नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सतत, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास के लिए एक आदर्श राज्य बनने की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है।

> *"विकास दृश्यमान, सुलभ और परिवर्तनकारी होना चाहिए। इन नई पहलों के माध्यम से, हम एक ऐसे छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ हर गाँव में पानी हो, हर परिवार के पास घर हो और हर नागरिक को समृद्ध होने के अवसर मिले।*
>
> **-श्री विष्णु देव साय**
> *मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़*

मोर गांव, मोर पानी

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य समुदाय द्वारा संचालित जल संरक्षण और भू-जल पुनर्भरण सुनिश्चित करना है। सोख्ता गड्ढे, बांध, चेक डैम जैसी 42,561 पुनर्भरण संरचनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। सरकार की अभियान से गांवों में टिकाऊ पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और जल संरक्षण के जरिए गांवों को सुख के खतरे से मुक्त बनाया जा सकेगा। जो संरचनाओं आज धरातल पर तैयार हुई हैं, वह आने वाले दिनों में गांव के लिए जल संरक्षण का मूल आधार बनेंगी।

पीएम-जनमन (पीवीटीजीएस के लिए आवास)

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, कोरवा, आदि) के लिए पीएम जनमन आवास के रूप में विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना सबसे दूरस्थ और हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराती है। योजना से राज्य के जनजातीय बाहुल्य बस्तर और सरगुजा संभागों में विशेष संरक्षित जनजातीय समुदाय के परिवारों को अपना पक्का घर उपलब्ध हो रहा है।

मोर गांव, मोर मकान (मेरा गांव, मेरा घर)

ग्रामीण छत्तीसगढ़ में शत-प्रतिशत पक्के आवास कवरेज प्राप्त करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पीएमएवाई-जी के साथ-साथ मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को मजबूत बनाने के लिए इस अभियान के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं।

ऑनलाइन शहरी अवसंरचना निगरानी पोर्टल

सभी शहरी विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक रियल टाइम डिजिटल पोर्टल की हाल ही में शुरुआत की गई है। https://adho.cguadfinance.in के माध्यम से 7067 से अधिक परियोजनाओं पर सार्वजनिक पहुंच के साथ पारदर्शी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। इसका उद्देश्य शासकीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना और शिकायत निवारण में तेजी लाना है।

नए शहरी विकास अनुदान

छत्तीसगढ़ में शहरी विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए ₹840 करोड़ के नए आवंटन की घोषणा की गई है। इससे राज्य में शहरों के अधोसंरचनात्मक बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। सड़क सुदृढ़ीकरण, नए पार्कों और उद्यानों की स्थापना, खेल के मैदान, सार्वजनिक सौन्दर्यीकरण एवं जल निकासी पर इस अनुदान से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में 30 शहरी निकायों में 53 नई परियोजनाएं शुरू की गईं।

आंगनवाड़ी अवसंरचना विस्तार

छत्तीसगढ़ में नए आंगनवाड़ी केन्द्रों और ग्रामीण बाल देखभाल सेवाओं के उन्नयन के लिए 298 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जमीनी स्तर पर इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। आंगनबाड़ियों में गर्भवती, माताओं व शिशुओं को संतुलित आहार भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे राज्य पूरी तरह कुपोषण मुक्त हो सके।

डिजिटल गवर्नेंस की मजबूती

राज्य में नागरिकों को सुरक्षित, ई-एमबी प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल शासन की सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण कार्यों और रोजगार ट्रैकिंग का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया है। कार्यस्थल पर उपस्थिति के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) को शत् प्रतिशत अपनाया चुका है। इसके लिए 'सिक्योर' (ग्रामीण दरों का उपयोग करके अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर) पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

मूलढ़ांचा परियोजनाएं

छत्तीसगढ़ राज्य में मूल ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 2025-26 हेतु 1840 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें सड़कें, प्रकाश व्यवस्था, पार्क, सामुदायिक हॉल जैसी 53 प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2018 से अब तक राज्य में 7067 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग पोर्टल

- रायपुर और बिलासपुर में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- नगरपालिका सेवाओं जैसे जल बिल, संपत्ति कर, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ई-गवर्नेंस परियोजना शुरू की गई।
- स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 380 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 98% परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है।

प्रमुख उपलब्धियां

सभी के लिए आवास

- 26 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के घर
- पीएमएवाई-जी और पीएम-जनमन योजनाओं का विस्तार
- स्वीकृत मकानों में 94% का निर्माण पूरा

जल संरक्षण

- 'मोर गांव मोर पानी' अभियान की शुरुआत
- 42,561 पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण

समावेशी विकास

- 180 करोड़ की सहायता से पंचायती राज की मजबूती की पहल

रोजगार सृजन (मनरेगा)

- 1.32 करोड़ व्यक्ति कार्य सृजित किए गए
- ग्रामीण विकास कार्यों में 53% महिला भागीदारी सुनिश्चित की एससी/एसटी की भागीदारी पर जोर
- सड़कें, वृक्षारोपण जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण